OXFAM INDIA'S DISCRIMINATION REPORT 2022

Recently, Oxfam India's released the 'India Discrimination Report 2022.

Key Points

Image Source: The Quint

- Discrimination in the labour market is when people with identical capabilities are treated differently because of their identity or social backgrounds.

- **Source of Data:** The report's findings are based on Government of India data on employment and labour from 2004-05 to 2019-20.

Key findings

Women:

LFPR (Labour Force Participation Rate)	2004-05	2021
Women	**42.7%**	**25.1%**

This shows the withdrawal of women from the workforce despite rapid economic growth during the same period.

- Overall discrimination in wages for people from SC, ST and Muslim communities declined in regular/salaried jobs, it increased for women in this period — from 67.2% in 2004-05 to 75.7% in 2019-20.

SC/ST:

- In 2019-20, the average income for people from SC or ST communities with regular employment in urban areas was Rs 15,312 compared to Rs 20,346 for those from the 'general' category.
- This means the general category is earning 33% more than SCs or STs.

Muslims:

- In 2019-20, 68.3% of Muslims in urban areas faced discrimination, up from 59.3% in 2004-05.

Reasons for Discrimination:

- Gender-based discrimination is the reason for 98 percent of the employment gap.
- 'societal and employers' prejudices" for women's lower wages.
- Poor access to education or employment.

Conclusion:

- The fallout of discrimination in Indian society is not just social and moral but also economic, leading to adverse consequences to society.
- The government, political parties, policymakers and civil society must work together to build a discrimination-free India.

OXFAM:

- Oxfam is a grouping of 20 separate nonprofit organisations dedicated to eradicating poverty worldwide.
- Founded in 1942, it is headed by Oxfam International.
- India has been home to Oxfam since 1951. It initially travelled to India to assist with the famine in Bihar.
- Oxfam India formed a separate affiliate and an Indian NGO in 2008.
- A sizable nonprofit organisation, that runs a wide range of programmes.
- Headquater: Nairobi, Kenya.
- Vision: A society in which the economy is centred on the welfare of people and the environment. a place where girls and women can live without harassment and abuse. where there is a climatic catastrophe. Whereas inclusive governance structures enable accountability for people in authority.
- The impact of climate change is much more severe on the poorer nations because of their geographical locations and weaker capacity to cope.
- Further, loss and damage caused by climate change go into billions of dollars, or even more.
- The economic loss from cyclone Amphan in India and Bangladesh in 2020 has been assessed at $15 billion.
- The nations that will be most severely affected by climate change are those with small past emissions contributions and severe resource constraints.
- According to estimates, the emissions from just the United States alone "damaged other countries to the tune of more than $1.9 trillion."
- There are also non-economic losses, such as deaths, displacement and migration, adverse effects on one's health, and harm to one's cultural heritage.

इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022

हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया ने 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022' जारी की।

प्रमुख बिंदु

छवि स्रोत: द क्विंट

- श्रम बाजार में भेदभाव तब होता है जब समान क्षमता वाले लोगों के साथ उनकी पहचान या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अलग व्यवहार किया जाता है।

- डेटा का स्रोत: रिपोर्ट के निष्कर्ष 2004-05 से 2019-20 तक रोजगार और श्रम पर भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

मुख्य निष्कर्ष

स्त्रियां :

LFPR (श्रम शक्ति भागीदारी दर)	2004-05	2021
स्त्रियां	42.7%	25.1%

यह आंकड़ा इसी अवधि के दौरान तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद कार्यबल से महिलाओं की वापसी को दर्शाता है।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदायों के लोगों के लिए मजदूरी में भेदभाव में नियमित / वेतनभोगी नौकरियों में गिरावट आई है। इस अवधि में महिलाओं के लिए यह भेदभाव बढ़ गया है । 2004-05 के 67.2% से 2019-20 में यह आंकड़ा 75.7% हो गया।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति:

- 2019-20 में, शहरी क्षेत्रों में नियमित रोजगार वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की औसत आय 15,312 रुपये थी, जबकि 'सामान्य' श्रेणी के लोगों के लिए यह 20,346 रुपये थी।
- इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग एससी या एसटी की तुलना में 33% अधिक कमा रहा है।

मुसलमान:

- 2019-20 में, शहरी क्षेत्रों में 68.3% मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो 2004-05 में 59.3% था।

भेदभाव के कारण:

- 98 प्रतिशत रोजगार अंतर का कारण लिंग आधारित भेदभाव है।
- महिलाओं के कम वेतन के लिए 'सामाजिक और नियोक्ताओं के पूर्वाग्रह'।
- शिक्षा या रोजगार तक खराब पहुंच।

निष्कर्ष:

- भारतीय समाज में भेदभाव का नतीजा न केवल सामाजिक और नैतिक है, बल्कि आर्थिक भी है, जिससे समाज पर प्रतिकूल परिणाम होते हैं।
- भेदभाव मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकार, राजनीतिक दलों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज को मिलकर काम करना चाहिए।

ऑक्सफैम:

- ऑक्सफैम 20 अलग-अलग गैर-लाभकारी संगठनों का एक समूह है जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए समर्पित है।
- 1942 में स्थापित, इसका नेतृत्व ऑक्सफैम इंटरनेशनल करता है।
- भारत 1951 से ऑक्सफैम का घर रहा है। यह शुरू में बिहार में अकाल से निपटने के लिए भारत आया था।
- ऑक्सफैम इंडिया ने 2008 में एक अलग सहयोगी और एक भारतीय एनजीओ का गठन किया।
- एक बड़ा गैर-लाभकारी संगठन, जो कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला चलाता है।
- मुख्यालय: नैरोबी, केन्या।
- दृष्टि: एक ऐसा समाज जिसमें अर्थव्यवस्था लोगों और पर्यावरण के कल्याण पर केंद्रित हो। एक ऐसी जगह जहां लड़कियां और महिलाएं बिना उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के रह सकती हैं। जहां जलवायु संकट है। जबकि समावेशी शासन संरचनाएं सत्ता में बैठे लोगों के लिए जवाबदेही को सक्षम बनाती हैं।